कांग्रेस हमारी ''2 साल बनाम 5 साल'' रिपोर्ट का जवाब दे- भजनलाल

मानसरोवर में आयोजित महिला सम्मान समारोह में महिलाओं ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बाँधे

जयपुर, 26 अगस्त। रक्षाबंधन के पर्व पर मानसरोवर में आयोजित महिला सम्मान समारोह बुधवार को राजनीतिक संदेश का भी बड़ा मंच बन गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जहां बड़ी संख्या में महिलाओं से रक्षासूत्र बंधवाकर महिला सम्मान और सशक्तिकरण का संदेश दिया, वहीं

■ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को ऐसे जर्जर व जीर्ण-शीर्ण मकान की तरह बना दिया था, जो चारों तरफ से टूटा-फूटा था। ढाई वर्षों में सरकार ने समृद्ध और सशक्त राजस्थान की नींव रखी है।

मानसरोवर में बुधवार को आयोजित महिला सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रक्षासूत्र बांधे।

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, पेपरलीक और कानून व्यवस्था को लेकर जमकर निशाना साधा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने राजस्थान को एक ऐसे जर्जर और जीर्ण-शीर्ण मकान की तरह बना दिया था, जो चारों तरफ से टूटा-फूटा था। उस बदहाली को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के विकास का स्पष्ट रोडमैप तैयार किया। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में सरकार ने पानी, बिजली, रोजगार, किसान और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में समृद्ध एवं सशक्त राजस्थान की मजबूत नींव रखी है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने विधानसभा में ''2 साल बनाम 5 साल'' का रिपोर्ट कार्ड रखा और योजनाओं तथा विकास कार्यों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया। लेकिन कांग्रेस के नेता जवाब देने और बहस करने के बजाय मैदान छोड़कर चले गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के नेता राजस्थान में ''वन स्टेट, वन इलेक्शन'' को असंभव बताते थे, लेकिन अब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में युवाओं को सबसे अधिक नुकसान पेपरलीक प्रकरणों से हुआ। कई परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं ने युवाओं के भविष्य पर संकट खड़ा किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

उन्होंने कहा कि सरकार किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और एमएसपी पर बोनस के माध्यम से किसानों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

रक्षाबंधन कार्यक्रम का भावनात्मक क्षण तब आया, जब बड़ी संख्या में महिलाओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को रक्षासूत्र बांधे। मुख्यमंत्री ने माताओं और बहनों को रक्षाबंधन पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक होने के साथ ही, समाज में बहनों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के संकल्प को मजबूत करने का अवसर है।

कार्यक्रम में पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसन्न मेहता सहित, अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं।

एनटीए यूजीसी-नेट की ''आंसर की'' शीघ्र जारी करेगी

नई दिल्ली, 26 अगस्त। यूजीसी-नेट समेत कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में शामिल हुए लाखों उम्मीदवारों का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) इन परीक्षाओं के फाइनल आंसर-की और परिणाम जल्द अपनी

■ साथ ही सीएसआईआर-नेट, आईसीआर पीजी तथा पीएचडी के नतीजे भी जारी किए जाएंगे।

आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करने वाली है।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) जल्द ही यूजीसी-नेट जून 2026 के फाइनल आंसर-की और परीक्षा परिणाम जारी करेगी। इसके साथ हीद्ध काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च (सीएसआईआर-नेट), आईसीएआर पीजी और ऑल इंडिया कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (पीएचडी) 2026 के नतीजे भी जारी किए जाएंगे।

नतीजे जारी होने के बाद सफल उम्मीदवारों को आगे की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी भी दी जाएगी। परीक्षार्थियों को सलाह दी गई है कि वे ताजा अपडेट के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

लोकसभा सचिवालय ने भी टीएमसी के 20 बागी सांसदों को नोटिस भेजा

अभिषेक बनर्जी की 18 जून की याचिका की प्रति भेज उनसे सात दिन में जवाब मांगा

नई दिल्ली, 26 अगस्त। लोकसभा सचिवालय ने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को अभिषेक बनर्जी की ओर से दायर अयोग्यता याचिकाओं पर नोटिस भेजकर सात दिनों में जवाब मांगा है। इन सांसदों पर आरोप है कि वे टीएमसी से अलग होकर एनसीपीआई के साथ चले गए हैं।

टीएमसी इसे स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ना बताते हुए दलबदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता का आधार मान रही है, जबकि बागी सांसद अपने कदम को वैध विलय बता रहे हैं। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां अदालत ने कहा है कि अहम सवाल नोटिस जारी करना नहीं, बल्कि कार्यवाही को तय समय सीमा में पूरा करना है।

25 अगस्त को जारी इन नोटिसों के साथ अभिषेक बनर्जी की ओर से 18 जून को दायर की गई याचिका की प्रति भी सांसदों को भेजी गई है। यह याचिका लोकसभा सदस्यों के दलबदल के

■ लोकसभा सचिवालय की कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस मामले में नोटिस जारी करने के एक दिन बाद हुई।

आधार पर अयोग्यता नियम, 1985 के नियम 6 के तहत दाखिल की गई थी। लोकसभा सचिवालय ने सभी 20 सांसदों से नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर याचिका पर अपनी टिप्पणी और जवाब दाखिल करने को कहा है।

यह घटनाक्रम सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभिषेक बनर्जी की उस याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति जताने के एक दिन बाद सामने आया है, जिसमें दलबदल के आधार पर अयोग्यता की याचिकाओं पर जल्द फैसला लेने की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति जताई। बनर्जी ने अयोग्यता की कार्यवाही पर कथित देरी को चुनौती देते हुए अदालत से मामले में तेजी लाने की मांग की थी।

मोहन भागवत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आ ान करता है।'' अमेरिका के प्रमुख शहर न्यूयॉर्क में प्रवास के दौरान सरसंघचालक यूनिवर्सल वननेस (सार्वभौमिक एकता) कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और शनिवार को मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में लगभग 5000 लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। संघ प्रमुख डॉ. भागवत संघ के शताब्दी वर्ष के वैश्विक संपर्क कार्यक्रम के तहत अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की यात्रा कर रहे हैं। अमेरिका उनके प्रवास का प्रथम पड़ाव है।

'राजस्थान के कार्यवाहक चीफ ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

भी शामिल है, की धमकी देते हैं और इसके लिए सीजेआई के साथ अपनी निकटता का दावा करते हैं।

न्यायमूर्ति मेहता के पत्रों में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य मामले में की गई टिप्पणी का भी हवाला दिया गया है। सीजेआई सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा था कि सेवानिवृत्ति के करीब कुछ न्यायाधीशों द्वारा बाहरी कारणों से प्रभावित होकर आदेश पारित करने और रिटायर होने से पहले छक्के मारने की कोशिश करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

न्यायमूर्ति मेहता ने लिखा कि न्यायमूर्ति शर्मा के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनने के दिन से ही ऐसा लगता है कि उन्हें ''छक्के मारने का लाइसेंस'' मिल गया है।

सबूत के तौर पर, पत्रों में राजस्थान हाई कोर्ट की दो डिविज़न बैंचों के आदेशों का उल्लेख किया गया है। उदयपुर शहर की ''बेशकीमती जमानों'' से संबंधित अपीलों के एक समूह में मामलों को जयपुर पीठ में न्यायमूर्ति शर्मा की अपनी पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जबकि न्यायमूर्ति शर्मा के ही एक पुराने फैसले में कहा गया था कि जो मामले जोधपुर स्थित प्रधान पीठ से संबंधित हैं, उन्हें जयपुर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

17 अगस्त के पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि राजस्थान हाई कोर्ट के एक मौजूदा न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमा शंकर व्यास ने साथी न्यायाधीशों से न्यायमूर्ति शर्मा द्वारा उनकी पत्नी, जो जिला न्यायपालिका की वरिष्ठ अधिकारी हैं, के प्रति कथित प्रतिशोधात्मक रवैये की शिकायत की थी। न्यायमूर्ति व्यास के अनुसार, राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने अपनी ''मनमर्जी और सनक'' के कारण जोधपुर में नए अदालत भवन के उद्घाटन को रोक दिया, जिससे न्यायमूर्ति मेहता के शब्दों में संस्था को ''अक्षम्य नुकसान'' हुआ।

इसके अलावा, अधिवक्ता पूजा त्रिपाठी द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को भेजी गई और जिसकी प्रतिलिपि न्यायमूर्ति मेहता समेत 16 अन्य लोगों को भेजी गई, में की गई एक शिकायत में आरोप लगाया गया है कि न्यायमूर्ति शर्मा ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के पद का इस्तेमाल कर जयपुर और अजमेर में स्थायी लोक अदालतों में अपने करीबी लोगों की नियुक्तियां सुनिश्चित कीं। इनमें उनका बचपन का एक मित्र और दो जिला न्यायाधीशों के पति/पत्नी शामिल बताए गए हैं। उसी शिकायत में आरोप लगाया गया है कि न्यायमूर्ति शर्मा ने हाई कोर्ट में पदोन्नित के लिए चार महिला अधिवक्ताओं के नाम भी भेजे।

त्रिपाठी ने आगे कहा है कि इन चारों महिला अधिवक्ताओं में से कोई भी सक्रिय वकालत नहीं कर रही है और उनमें से प्रत्येक का संबंध किसी वरिष्ठ वकील या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से बताया गया है, जो न्यायमूर्ति शर्मा के करीबी हैं।

न्यायमूर्ति मेहता के पत्रों में कहा गया है कि गंभीर सबूतों के बावजूद, न्यायमूर्ति शर्मा को राजस्थान हाई कोर्ट का स्थायी मुख्य न्यायाधीश बनाने की प्रक्रिया चल रही है।

इसलिए उन्होंने कोलीजियम से न्यायमूर्ति शर्मा को राजस्थान से बाहर तत्काल स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है, ताकि संस्था को और नुकसान से बचाया जा सके।

न्यायमूर्ति मेहता ने लिखा, मैं बार-बार आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि राजस्थान हाई कोर्ट के लिए किसी अन्य राज्य से मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने का निर्णय लिया जाए, ताकि इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को रोका जा सके। इस अनुरोध की लगातार अनदेखी करना, मेरी राय में, संस्था के हित के पूरी तरह विपरीत है।

नेपाल में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बाद भारत पड़ोसी देश के लिए राहत सामग्री भेजने की तैयारी कर रहा है।

नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सहायता के लिए टोल-फ्री आपातकालीन नंबर 1234, हॉटलाइन 1144 तथा टूरिस्ट पुलिस नंबर 9851289445 भी जारी किया है।

गुरुग्राम के व्यस्ततम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया, जिससे उसकी लंबे समय से चली आ रही बुनियादी कमजोरियां सामने आ गईं।

स्थानीय नगर निगम ने और ज्यादा अव्यवस्था को रोकने और मरम्मत दलों के आने-जाने की सुविधा के लिए कड़े प्रशासनिक कदम उठाए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने कॉरपोरेट कार्यालयों और अन्य शैक्षिणक संस्थानों के लिए एक एडवाइज़री जारी की।

एडवाइज़री में कहा गया है कि, ''24.08.2026 को गुरुग्राम जिले में हुई भारी बारिश को देखते हुए जलभराव और यातायात जाम की संभावना है। इसलिए जिले के सभी कॉरपोरेट कार्यालयों तथा सरकारी और निजी स्कूलों/संस्थानों को सलाह दी जाती है कि वे अपने कर्मचारियों को 25.08.2026 से घर से काम करने के लिए कहें, ताकि यातायात जाम से बचा जा सके और नागरिक एजेंसियां सड़कों तथा नालियों की मरम्मत का काम सुचारू रूप से कर सकें।''

कोटा में एक और ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

तैयारी कर रही थी। उसकी बहन जब कोचिंग से वापस लौटी तो फ्लैट का लॉक नहीं खुला। बड़ी बहन को फोन किया तो उसका जवाब नहीं मिला। छात्रा ने काफी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद लॉक नहीं खुला। उसने अपनी बड़ी बहन की अन्य सहेलियों को फोन किया, किन्तु उनसे भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद लॉक खोलने वाले को बुलाया गया। जब उसने लॉक खोला तो छात्रा फंदे पर लटकी मिली। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई।

थानाधिकारी देवेश भारद्वाज ने बताया कि छात्रा के फ्लैट को सीज़ कर दिया गया था। उसके पेरेंट्स के आने पर उनकी उपस्थिति में ही फ्लैट का लॉक खोला गया। मृतक छात्रा का एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने नीट के एग्ज़ाम में अपेक्षित अंक न आने की बात है। गत नीट परीक्षा में छात्रा के 450 अंक आए थे और वह नीट की तैयारी कर रही थी।

हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मार के हत्या

अंकित शाम को जिम से बाहर निकला तो बाइक सवार चार बदमाशों ने उस पर 20 राउंड गोलियां चलाईं

शामली, 26 अगस्त। हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। शामली में बुधवार शाम करीब सात बजे हरियाणा के सिंगर अंकित बालियान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लगभग 20 राउंड फायरिंग की गई। पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

बुधवार को बाबरी थाना क्षेत्र के गांव बंतीखेड़ा निवासी हरियाणवी कलाकार 35 वर्षीय अंकित बालियान पुत्र सत्यवीर फौजी शाम साढ़े चार बजे कोतवाली क्षेत्र के आर्यपुरी में नाला पटरी स्थित मसल्स जिम में आए थे। शाम 6:48 बजे जैसे ही वे जिम से बाहर निकलकर अपनी

■ घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश 200 मीटर पैदल भागते हुए फरार हो गये। आक्रोशित स्वजनों ने शव सड़क पर रखकर देर रात तक जाम लगाया।

स्कार्पियो गाड़ी में बैठने लगे, तभी बाइक सवार चार बदमाश आए और चारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। करीब दो मिनट तक बदमाशों ने 20 राउंड फायरिंग की, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। फायरिंग में पांच गोलियां अंकित की गाड़ी में लगीं और करीब आठ गोली अंकित को लगी। अंकित का शव नाली के पास सड़क पर पड़ा था। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश 200 मीटर तक पैदल भागते हुए फरार हो गए। घटना से आक्रोशित स्वजन ने शहर के वर्मा मार्केट के पास शव को सड़क पर रखकर देर रात तक जाम लगाया।

तृतीय श्रेणी शिक्षक ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नहीं करने के लिए पाबंद कर दिया था। याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 6 नवंबर को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन के करीब पांच हजार पदों पर भर्ती निकाली थी। इसकी लिखित परीक्षा गत 17 जनवरी को हुई। इसके बाद भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी 15 जून को जारी हुई थी। इसके आधार पर 11 जून 2026 को सलेक्शन बोर्ड ने भर्ती का परिणाम घोषित किया। याचिका में कहा गया है कि इस भर्ती के अंतिम परिणाम में 17 प्रश्न-उत्तर विवादित हैं। इनमें से 11 प्रश्नों को डिलीट कर दिया और बाकी अन्य के उत्तरों को बोर्ड ने सही नहीं माना है। अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्न-उत्तरों के संबंध में आपत्ति भी लगाई, लेकिन उनकी आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञ की राय के आधार पर सही तरीके से नहीं किया गया। अब राज्य सरकार व बोर्ड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने जा रहा है। नियुक्ति मिलने के बाद तीसरे पक्षकार के अधिकार भी सृजित हो जाते हैं, इसलिए भर्ती में नियुक्ति देने पर रोक लगाई जाए।

भागलपुर में मजदूरों की नाव गंगा में पलटी, 6 लापता

भागलपुर, 26 अगस्त। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल अंतर्गत खरीक प्रखंड में बुधवार को बड़ा नाव हादसा हो गया। राघोपुर तटबंध के समीप गंगा नदी की तेज धारा में मजदूरों से भरी नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार और अफरा-तफरी मच गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, नाव पर सवार 18 मजदूरों में से 12 ने तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि छह मजदूर लापता बताए जा रहे हैं।

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ

■ नाव पर सवार 18 मजदूरों में से 18 ने तैर कर अपनी जान बचाई

की टीम मौके पर पहुंची और लापता मजदूरों की तलाश में युद्धस्तर पर खोज और बचाव अभियान शुरू किया। प्रशासनिक अधिकारी भी घटनास्थल पर कैंप कर स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि राघोपुर गांव के समीप दो दिन पहले गंगा नदी का तटबंध टूट गया था। इसके बाद इलाके में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया था। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल के आवास समेत, आसपास के कई इलाकों में भी बाढ़ का पानी पहुंच गया था।बाढ़ की स्थिति को देखते हुए तटबंध की मरम्मत, बाढ़ से बचाव और कटाव निरोधी कार्य युद्धस्तर पर चलाया जा रहा था। इसी काम में जुटे मजदूर बुधवार को नाव से नदी में रेत की बोरियां ले जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, रेत की बोरियां लेकर नाव नदी के बीच पहुंची थी। इसी दौरान गंगा की तेज धारा के दबाव के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई।

सभी प्रयासों के बाद ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, जो अपने कच्चे तेल की 85 प्रतिशत से अधिक जरूरत आयात से पूरी करती है। इसलिए कंपनियां ऐसे समय में बड़ी और लंबी अवधि की परियोजनाओं में पैसा लगाने से हिचक रही हैं, जब ऊर्जा और अन्य कच्चे माल की लागत में अचानक बड़ा बदलाव आ सकता है।

व्यापार को लेकर अनिश्चितता एक और बड़ी मुश्किल है। कंपनियों को बदलती टैरिफ दरों, आपूर्ति श्रृंखलाओं और निर्यात बाजारों का आकलन करना पड़ रहा है। साथ ही, सस्ते आयात से घरेलू उत्पादकों पर दबाव पड़ सकता है और उत्पादन क्षमता बढ़ाने का उनका प्रोत्साहन कम हो सकता है। बैंकिंग क्षेत्र के एक हालिया आकलन में कॉपोरेट केपैक्स (कैपिटल एक्सपैंडिचर) फैसलों पर असर डालने वाले कई फैक्टर्स की पहचान की गई है, जैसे कि असमान डिमांड, कमोडिटी की कीमतों में उतार-चढ़ाव, व्यापार से जुड़ी अनिश्चितता, जिओपोलिटिकल तनाव और सस्ते इम्पोर्ट से मुकाबला।

कैपिटल की लागत भी एक और बड़ी बाधा है। सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत में पूंजी की अपेक्षाकृत ऊंची लागत लंबे समय में पूरी होने वाली निजी परियोजनाओं को हतोत्साहित कर सकती है, भले ही कंपनियों की वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर हो। दूसरे शब्दों में, कंपनियों के पास निवेश करने की वित्तीय क्षमता हो सकती है, लेकिन फिर भी वे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को इतना आकर्षक नहीं मानतीं कि परियोजनाओं को तुरंत शुरू करें।

रुपये की कमज़ोरी ने भी अनिश्चितता बढ़ा दी है। इस साल डॉलर के मुकाबले रुपया 6 प्रतिशत से अधिक कमज़ोर हो चुका है। इससे इम्पोर्ट की गई मशीनरी और कच्चे माल की लागत बढ़ गई है, जबकि कंपनियों को एक्सपोर्ट और घरेलू डिमांड में अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप कारोबार जगत का भरोसा कमज़ोर हुआ है। कंपनियां खराब आर्थिक परिस्थितियों और कमज़ोर मुद्रा को चिंता का कारण बता रही हैं। इससे पता चलता है कि सरकारी खर्च ग्रोथ का एक अहम आधार क्यों बना हुआ है। सड़कों, रेलवे, इन्फ्रास्टक्चर और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर पब्लिक कैपिटल एक्सपैंडिचर से स्टील, सीमेंट, मशीनरी और कंस्ट्रक्शन सर्विस की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन सरकार हमेशा के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमैंट की जगह नहीं ले सकती। निवेश में टिकाऊ तेजी के लिए जरूरी है कि कंपनियां खुद उत्पादन क्षमता बढ़ाएं, रोजगार पैदा करें और लंबे समय के कारोबारी जोखिम उठाएं।

फिर भी उम्मीद की कुछ वजहें हैं। भारत की पिछली निवेश मंदी के समय की तुलना में कंपनियों की वित्तीय स्थिति काफी बेहतर है। वहीं, अप्रैल-जून तिमाही में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात सालाना आधार पर 11 प्रतितशत से अधिक बढ़ा है। पहले की गई जीएसटी और आयकर में कटौती से भी उपभोक्ता मांग को समर्थन मिला है।

इसलिए तत्काल चुनौती यह है कि कंपनियों को भविष्य की मांग, कच्चे माल की लागत, व्यापार की स्थिति और नीतिगत स्थिरता को लेकर इतना भरोसा दिया जाए कि वे लंबे समय के लिए निवेश करने का फैसला कर सकें।

भारत की 7.1 प्रतिशत विकास दर अब भी प्रभावशाली है। लेकिन विकास की अगली गति लंबे समय तक केवल उपभोक्ताओं और सरकार पर निर्भर नहीं रह सकती। असली परीक्षा यह है कि क्या निजी कंपनियां मौजूदा उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल करने के बजाय नई क्षमता बनाने की ओर बढ़ती हैं या नहीं। जब तक ऐसा नहीं होता, भारत की विकास दर ऊपर से मजबूत दिख सकती है, लेकिन असल में वो उतनी व्यापक नहीं होगी, जितना कि मुख्य जीडीपी आंकड़ों से पता चलता है।

दिल्ली के लोनी क्षेत्र में 16 ओद्यौगिक इकाइयाँ सील की गईं

नई दिल्ली, 26 अगस्त। वायु प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने मंगलवार को लोनी क्षेत्र में 'ऑपरेशन क्लीन एयर' के तहत विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान के

■ सभी को पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया।

दौरान 28 औद्योगिक परिसरों की जांच की गई और सभी में पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन पाया गया। इसमें से 16 औद्योगिक इकाइयों/परिसरों को सील कर दिया गया। आयोग ने बुधवार को जानकारी दी कि कार्रवाई के लिए 7 फ्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए थे। इनमें मजिस्ट्रेट, पुलिस और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद रहे। जांच में सामने आया कि 21 इकाइयां वैध मंजूरी के बिना संचालित हो रही थीं। वहीं 14 मामलों में लकड़ी और कोयले, जो प्रतिबंधित/अनुमोदित नहीं किए गए, जैसे ईंधन का इस्तेमाल पाया गया।

मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्णय लेने वाली शीर्ष संस्थाओं में बदलाव की संभावना है। संसदीय बोर्ड की भूमिका विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों को हरी झंडी देने से लेकर प्रधानमंत्री के चयन तक महत्वपूर्ण है।

संसदीय बोर्ड के पास व्यापक अधिकार हैं, लेकिन उसका आकार छोटा है। नितिन नबीन की मौजूदा टीम ''प्लेइंग इलेवन'' में बदलाव की गुंजाइश ज्यादा नहीं है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बोर्ड में बने रहेंगे।

राजनाथ सिंह इसके सबसे वरिष्ठ मौजूदा सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मुश्किल से छह महीने दूर हैं। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में ऊंची जाति के ठाकुर मतदाताओं के एक हिस्से के भाजपा से दूर होने से पार्टी को नुकसान हुआ था।

किसी और ठाकुर नेता को शामिल करने से ज्यादा राजनीतिक हलचल उन्हें हटाने से पैदा होगी। इसलिए राजनाथ सिंह को हटाए जाने की संभावना कम है। संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी बने रहेंगे। इसका मतलब है कि अभी सात पदों पर बदलाव की गुंजाइश है। इन पदों पर फिलहाल जेपी नड्डा, बीएस येदियुरप्पा, सर्बानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इकबाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव और सत्यनारायण जटिया हैं।

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा पार्टी के पूर्व अध्यक्ष होने के कारण बोर्ड में हैं। उनके बने रहने के पक्ष में एक महत्वपूर्ण, हालांकि निर्णायक नहीं, कारण यह है कि उनके गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में नवंबर 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। दूसरा कारण यह है कि वह के शीर्ष दो नेताओं की कार्यशैली को अच्छी तरह समझते हैं। इससे संभावित बदलाव के लिए मैदान में केवल छह पद बचते हैं। लेकिन असली मुश्किल यह तय करने में होगी कि किसे बाहर किया जाए। भाजपा के पूर्व कर्नाटक विजेता बीएस येदियुरप्पा इस साल फरवरी में 80 वर्ष के हो गए। उनके बाहर निकलने की रणनीति बनाते समय भाजपा और आरएसएस को इस तथ्य का भी ध्यान रखना होगा कि कर्नाटक की प्रभावशाली जाति लिंगायत समुदाय का प्रतिनिधित्व अभी भी भाजपा के शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय में उनके नेता के रूप में मौजूद है। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव मई 2028 में होने हैं। असम में इस साल अप्रैल में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल उत्तर-पूर्व के एक बड़े चेहरे हैं और यह क्षेत्र भाजपा के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्रों में शामिल है। उनकी आदिवासी पृष्ठभूमि उन्हें एक साथ दो फायदे देती है।

इकबाल सिंह लालपुरा फिलहाल भाजपा के अल्पसंख्यक चेहरे हैं, क्योंकि संसदीय बोर्ड में कोई मुस्लिम सदस्य नहीं है। वे पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और उन्होंने 1978 में सिख-निरंकारी संघर्ष के बाद, अलगाववादी नेता जरनैल सिंह भिंडरांवाले को गिरफ्तार किया था। वे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भाजपा फरवरी 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए उनकी जगह किसी युवा और अधिक प्रभावशाली सिख चेहरे को ला सकती है।

सुधा यादव हरियाणा से आती हैं। नरेन्द्र मोदी के गुजरात का मुख्यमंत्री बनने से भी पहले, 1999 में जब वे भाजपा के हरियाणा प्रभारी थे, तब उन्होंने महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से सुधा यादव का समर्थन किया था।

सबसे अधिक संभावना सत्यनारायण जटिया की जगह किसी और को लाने की है। भाजपा संसदीय बोर्ड में किसी अधिक प्रमुख पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, युवा या महिला चेहरे को शामिल कर एक राजनीतिक संदेश दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल संसदीय बोर्ड में मुख्यमंत्रियों को शामिल करने का है।

जनवरी 2006 में भाजपा अध्यक्ष के रूप में राजनाथ सिंह ने तत्कालीन गुजरात मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को संसदीय बोर्ड में शामिल किया था, लेकिन 2007 में उन्हें हटा दिया गया।

2013 में परिस्थितियां बदल चुकी थीं। मार्च में मोदी को फिर संसदीय बोर्ड में शामिल किया गया। इसके बाद उसी साल जून में उन्हें भाजपा की चुनाव अभियान समिति का प्रमुख बनाया गया और सितंबर में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया।

अगस्त 2022 में तत्कालीन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया और इसके बाद अनौपचारिक रूप से शीर्ष निकाय में कोई मुख्यमंत्री नहीं का नियम चलन में आ गया।

इसका तर्क यह दिया गया था कि मुख्यमंत्री संसदीय बोर्ड के सदस्य रहते हुए मुख्यमंत्रियों से जुड़े फैसलों पर स्वयं कैसे निर्णय ले सकते हैं?

लेकिन हाल ही में हुई एक बैठक के बाद संकेत मिल रहे हैं कि भाजपा का वैचारिक मार्गदर्शक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस को संसदीय बोर्ड में शामिल करने पर जोर दे रहा है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादकः- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालयः-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालयः-कुंम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालयः-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालयः-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालयः एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908